



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जयाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या:टीएस-सीसीटीएनएस-21/2013  
सेवा में,

दिनांक:अप्रैल २१, 2015

समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक  
एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक: 10-04-2015 को दूरभाष पर इन्टरनेट की व्यवस्था के सम्बन्ध में जनपदों से सीसीटीएनएस कन्ट्रोल रूम स्तर से ज्ञात किया गया तो कतिपय जनपदों द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अनभिज्ञता प्रकट की गयी तथा कतिपय जनपदों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि इन्टरनेट हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

2— उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: सात-62(3)2011 दिनांक: 23-03-2015 का अवलोकन करें, जो आपको सम्बोधित किये जाने के साथ-साथ इस मुख्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कि प्रदेश के थानों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों सहित इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था के लिए धनराशि रु0 67,84,198/- (रु सरसठ लाख, चौरासी हजार, एक सौ अठानवे ) प्रदेश के लिए आवंटित की गयी है।

3— अतः उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: सात-62(3)2011 दिनांक: 23-03-2015 की छायाप्रति ई-मेल के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि।

( डॉ कौरी )  
 पुलिस उप महानिरीक्षक,  
 तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश,  
 लखनऊ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— अपर पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
- 3— पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(195)

# उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-१

संख्या: सात-६२(३)२०११

दिनांक मार्च २३, २०१५

सेवा में,

१. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,  
उत्तर प्रदेश।
२. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उ०प्र०।

**विषय:** प्रदेश के थानों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कार्यालयों सहित कुल 2208 लोकेशन्स पर इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया पुलिस मुख्यालय के समसंबंधक पत्र दिनांक ०५.०१.२०१५ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या: ९१७६-पु-७-१४-०१ सीसीटीएनएस/ २०१४ दिनांक २८.३.२०१४ द्वारा इन्टरनेट कनेक्शन, विभाग में पूर्व से स्थापित लैण्ड लाइन कनेक्शन पर ब्रॉड बैण्ड के माध्यम से असीमित डाउनलोड के सबसे मितव्ययी योजना के अन्तर्गत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

२. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार थानों/कार्यालयों में इन्टरनेट कनेक्शन लगवाये जाने हेतु निहित आवर्तक एवं माह जनवरी/फरवरी २०१५ के बिलों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन द्वारा कुल ₹ ७१.२३ लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्रमांक	विवरण	संख्या
१.	समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय	७५
२.	जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	१२४
३.	जनपदीय क्षेत्राधिकारी कार्यालय	३८१
४.	जनपदीय थाना	१४३९
५.	जीआरपी थाना	६५
६.	रिपोर्टिंग आउट पोस्ट	१०५
७.	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे	०६
८.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय रेलवे	१३
	योग	२२०८

✓ अपर पुलिस महानिदेशक  
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश

२५.३.१५

३. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें के पत्र दिनांक २.३.२०१५ द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्तानुसार १०५ रिपोर्टिंग आउट पोस्ट में सीसीटीएनएस कनेक्शनलिटी उपलब्ध नहीं है। अतएव कुल १०५ रिपोर्टिंग आउटपोस्ट को छोड़कर अन्य शेष २१०३ (२२०८-१०५ = २१०३) लोकेशन्स पर इन्टरनेट की व्यवस्था कराया जाना अपेक्षित है।

४. उपरोक्तानुसार कुल २१०३ लोकेशन्स (१४३९ थानों/६५ जीआरपी थानों/ ७५ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद कार्यालयों/ ०६ पुलिस अधीक्षक, रेलवे कार्यालयों/१२४ जनपदीय अपर पुलिस अधीक्षकों/३८१ जनपदीय क्षेत्राधिकारियों/१३ क्षेत्राधिकारी रेलवे कार्यालयों) में शासनादेश दिनांक २८.३.२०१४ में वर्णित व्यवस्था के अधीन मानक मद “१२-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण” में प्रति लोकेशन मोडेम आदि की व्यवस्था ₹ २०००/- तथा भारत संचार निगम लिंग की असीमित डाउनलोड की सबसे मितव्ययी ब्रॉडबैण्ड योजना के अधीन माह जनवरी एवं फरवरी २०१५ के इन्टरनेट बिलों के भुगतान हेतु ₹ ५४५/- प्रतिमाह (सेवाकर अतिरिक्त) की दर से

AC-II

0002

25/3/15

02 माह पर निहित व्ययभार के भुगतान हेतु मानक मद '13-टेलीफोन पर व्यय' के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर पुलिस मुख्यालय के निम्नवत आवंटन आदेशों द्वारा कुल रु० 67,84,198/- का अनुदान आवंटित किया जा रहा है:-

क्रमांक	आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि	आवंटी कार्यालय	लेखाधीशक मानक मद	आवंटित अनुदान
1.	2563/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त जनपद उपरा०	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला पुलिस (थाना)-12-कार्यालय फर्माचर एवं उपकरण	28,78,000/-
2.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला पुलिस (थाना)-13-टेलीफोन पर व्यय	17,64,214/-
3.	2563/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य- 12-कार्यालय फर्माचर एवं उपकरण	11,60,000/-
4.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस-मुख्य-13- टेलीफोन पर व्यय	7,11,000/-
5.	2561/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उपरा०	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-111- रेलवे पुलिस-03-पुख्य-12-कार्यालय फर्माचर एवं उपकरण	38,000/-
6.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-111- रेलवे पुलिस-03-मुख्य-13- टेलीफोन पर व्यय	23,294/-
7.	2564/सात-62(3)2011 दिनांक 23.3.2015	समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उपरा०	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109- जिला पुलिस-08-जीवारपी थाना पुलिस-12-कार्यालय फर्माचर एवं उपकरण	1,30,000/-
8.	-तदैव-	-तदैव-	2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109- जिला पुलिस-08-जीवारपी थाना पुलिस-13-टेलीफोन पर व्यय	79,690/-
कुल योग				67,84,198/-

5. उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.1.2015 द्वारा पूर्ववत अवगत कराया गया है कि प्रदेश पुलिस के समस्त लैण्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शन पर भारत संचार निगम लि० की तरंग योजना दिनांक 1.7.2014 से लागू है। कनेक्शन पर भारत संचार निगम लि० की तरंग योजना दिनांक 1.7.2014 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 1500 कनेक्शन्स पर ब्राडबैण्ड इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिन कनेक्शन पर यह सुविधा प्रदान की जानी है, उन कार्यालयों के जा रही है। जिन कनेक्शन पर यह सुविधा प्रदान की जानी है, उन कार्यालयों के नाम एवं लैण्ड लाइन नम्बर पूर्व से भारत संचार निगम लि० को उपलब्ध करा दिये गये हैं। शेष अन्य लैण्ड लाइन कनेक्शन पर यदि ब्राड बैण्ड कनेक्शन लिया जाता है, तो उन टेलीफोन नम्बर पर ब्राड बैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन हेतु अतिरिक्त भुगतान निर्देशित किया गया है, उनमें प्रदेश के किसी भी थाने का लैण्ड लाइन कनेक्शन सम्मिलित नहीं है।

6. उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यालयों के जिन टेलीफोन कनेक्शन्स पर पूर्व से तरंग योजना प्रचलित है एवं उक्त 1500 की सूची में सम्मिलित हैं तथा इन्टरनेट के संचालन में कठिनाई आ रही है एवं वे टेलीफोन कनेक्शन उक्त 2103 लोकेशन्स में सम्मिलित हैं तो उन कनेक्शन पर उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 28.3.2014 में वर्णित व्यवस्था के अधीन इन्टरनेट कनेक्शन पर लगवाने हेतु भारत संचार निगम लि० से अनुरोध किया जा सकता है तथा कालान्तर में उन टेलीफोन नम्बर की

सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है ताकि तरंग योजना में उस टेलीफोन नम्बर के स्थान पर किसी अन्य नम्बर को सम्मिलित करने हेतु भारत संचार निगम लिंग से अनुरोध किया जा सके।

7. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत कार्यवाही करते हुये आवृद्धित किये जा रहे अनुदान का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

  
23/03/2015

( आशुतोष मिश्र )

अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,  
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

#### फैक्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उप्रा०, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उप्रा०, लखनऊ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जॉन्स, उप्रा०।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिषेन्ट्र, उप्रा०।

फैक्स: 0522-2347000/2628400

प्रतिलिपि श्री शाहिद जमाल, सहायक महाप्रबंधक (ई०बी०), कामरियल, कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार यूपी ईस्ट (इन्टरप्राइज बिजनेस इकाई), भोपाल हाउस, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार धानों/कार्यालयों में पूर्व से स्थापित लैण्ड लाइन कनेक्शन्स पर भारत संचार निगम लिंग की असीमित डाउनलोड की सबसे भित्तियाँ योजना के अन्तर्गत ब्राउड बैण्ड के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक अनुरोध प्राप्त होने पर तत्काल ब्राउबैण्ड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सर्वसम्मिलित को निर्देशित करने का कष्ट करें।